

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कार्य-निष्पादन समीक्षा - 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही

पीएफसी ने 13 फरवरी 2023 को 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की। तिमाही 3'23 और 9माह'23 के कार्य-निष्पादन संबंधी विशेषताएं निम्नानुसार हैं।

समेकित मुख्य विशेषताएं

क. वित्तीय कार्य-निष्पादन

- 1) पीएफसी समूह ने तिमाही3'22 से 7% की वृद्धि हासिल करते हुए तिमाही3'23 में, 5,241 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक समेकित कर पश्चात लाभ (पीएटी) प्रदान किया।
- 2) समेकित ऋण परिसंपत्ति बही 8 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई। 31.12.2022 को ऋण परिसंपत्ति बही 8,04,526 करोड़ रुपए है।
- 3) समेकित संवितरण 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया जिसमें 9माह'22 की तुलना में 28% की वृद्धि दर्ज करते हुए 9माह'23 के लिए यह 1,06,875 करोड़ रुपए हो गया। यह पीएफसी समूह के सुदृढ़ व्यावसायिक कार्य-निष्पादन को दर्शाता है।
- 4) दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में तालमेल के कारण सकल एनपीए अनुपात 4% से नीचे गिरकर 9माह'22 में 5.55% से 9माह'23 में 3.91% हो गया है।
- 5) समेकित निवल एनपीए अनुपात में 71 बीपीएस की कमी होकर 9माह'22 में 1.86% से 9माह'23 में 1.15% हो गया है। यह समेकित आधार पर अब तक का सबसे कम निवल एनपीए अनुपात है।
- 6) वितरण पक्ष पर, आज तक, पीएफसी समूह ने सामूहिक रूप से 1,02,831 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं और देरी से भुगतान अधिभार नियमों के तहत 28,179 करोड़ रुपए संवितरित किए। संस्वीकृत राशि का संवितरण 12 से 48 महीनों की समान मासिक किश्तों (ईएमआई) के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

स्टैंडअलोन मुख्य विशेषताएं

क. वित्तीय और व्यावसायिक कार्य-निष्पादन

➤ **वित्तीय कार्य-निष्पादन**

- 1) तिमाही3'23 में, पीएफसी ने 3,005 करोड़ रुपए का उत्कृष्ट तिमाही कर पश्चात् लाभ दर्ज किया और तिमाही3'22 की तुलना में 26% वृद्धि दर्ज की।
- 2) 9माह'23 के लिए, पीएफसी ने पिछले वित्तीय वर्ष के नौ माह के कर पश्चात लाभ के 7,412 करोड़ रुपए की तुलना में 8,113 करोड़ रुपए का कर पश्चात् लाभ दर्ज किया।
- 3) तिमाही3'23 में, पीएफसी ने 3.50 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया, जो वित्तीय वर्ष के लिए संचयी अंतरिम लाभांश 8.75 रुपए प्रति शेयर है।
- 4) दिनांक 31.12.2022 को सीआरएआर 24.41% पर है, जिसमें टीयर I पूंजी 21.34% और टीयर II पूंजी 3.07% है। पीएफसी स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता स्तरों को बनाए रखना जारी रखे हुए है।
- 5) 9माह'23 के लिए अर्जित परिसंपत्ति और निधियों की लागत क्रमशः 10.07% की यील्ड और 7.53% की लागत के साथ अपेक्षित सीमा के भीतर है। 9माह'23 के लिए स्प्रेड भी 2.54% के निर्देशित स्तरों के भीतर बना हुआ है।

➤ **व्यावसायिक कार्य-निष्पादन**

- 1) **9माह'23 के लिए संवितरण में 36% की वृद्धि दर्ज की गई** - 9माह'22 में 34,590 करोड़ रुपए की तुलना में 9माह'23 में 46,968 करोड़ रुपए संवितरित किया गया।
- 2) **पीएफसी की स्टैंडअलोन ऋण बुक में 6% की वृद्धि दर्ज की गई**
 - दिनांक 31.12.2021 तक 3,71,649 करोड़ रुपए की तुलना में दिनांक 31.12.2022 तक ऋण परिसंपत्ति बुक 3,93,387 करोड़ रुपए है।
 - आर्थिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने, पीएफसी पर पूर्वभुगतान दबाव कम होने और डिस्कॉम के लिए सरकार की पहल के कारण संवितरण की गति में तेजी आई है, जिससे पीएफसी की ऋण परिसंपत्ति बुक में वृद्धि हुई है।

ख. परिसंपत्ति सारांश

1) **9माह'23 के लिए एनपीए का स्तर 9माह'22 की तुलना में काफी कम हो गया**

- 9माह'23 के लिए पीएफसी के सकल एनपीए अनुपात में 9माह'22 से 185 बीपीएस की महत्वपूर्ण कमी देखी गई - 9माह'22 में 6.06% की तुलना में 9माह'23 के लिए सकल एनपीए स्तर 4.21% है।
- 9माह'23 के लिए निवल एनपीए स्तर भी 9माह'22 में 2% से 81 बीपीएस घटकर 9माह'23 में 1.19% हो गया।
- एनपीए स्तरों में कमी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने के हमारे समर्पित प्रयासों का परिणाम है। 9माह'22 के बाद से, पीएफसी ने 5,964 करोड़ रुपए की पांच दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान किया है। ये पांच परिसंपत्तियां एस्सार पावर एमपी लिमिटेड (1,345 करोड़ रुपए), आरएस इंडिया विंड एनर्जी (224 करोड़ रुपए), साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन (2,263 करोड़ रुपए), झाबुआ पावर लिमिटेड (764 करोड़ रुपए) और इंड-बराथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड (1,368 करोड़ रुपए) हैं। इन परिसंपत्तियों में से इंड-बराथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड का समाधान इस तिमाही में किया गया था।

2) **समाधान स्थिति पर अद्यतन**

- पूर्व में साझा किए गए मार्गदर्शन के अनुसार, वर्तमान तिमाही में 1,368 करोड़ रुपए के एक दबावग्रस्त परिसंपत्ति ऋण अर्थात इंड-बराथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड का समाधान किया गया था। यह 700 मेगावाट की थर्मल उत्पादन परियोजना है और इसका एनसीएलटी के अधीन समाधान किया गया था। इस परियोजना को जेएसडब्ल्यू ने अधिग्रहण कर लिया है। ऋण के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध था।
- वर्तमान में, तीसरे चरण में 16,564 करोड़ रुपए की 22 दबावग्रस्त परियोजनाएं हैं। 22 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं 10,973 करोड़ रुपए की हैं, जिनका एनसीएलटी के अधीन समाधान किया जा रहा है और शेष 10 परियोजनाएं 5,591 करोड़ रुपए की हैं, जिनका एनसीएलटी के बाहर समाधान किया जा रहा है।
- उपर्युक्त 22 परियोजनाओं में से, 2,789 करोड़ रुपए के बकाया ऋण की 2 परियोजनाएं समाधान के अग्रिम चरण में हैं।

ये दो परियोजनाएं निम्नानुसार हैं

- 413 करोड़ रुपए की डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। यह 96 मेगावाट की हाइड्रो एनर्जी परियोजना है और इसका समाधान एनसीएलटी के बाहर किया जा रहा है। परियोजना के लिए समाधान योजना को पीएफसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और अन्य ऋणदाता अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।
- लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड की 2,376 करोड़ रुपए। यह 1,920 मेगावाट थर्मल उत्पादन परियोजना है। पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल)-आरईसी कंसोर्टियम को आशय पत्र जारी किया गया है और समाधान योजना एनसीएलटी के तहत दायर की जा रही है।

ग. संवितरण योजनाओं पर अद्यतन

1) पीएफसी द्वारा आज तक 14,389 करोड़ रुपए विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों के तहत संवितरित

- अब तक, पीएफसी ने एलपीएस नियमों के तहत 46,788 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं और डिस्कॉम को देय राशि के भुगतान के लिए 14,389 करोड़ रुपए संवितरित किए।
- एलपीएस दिशानिर्देशों के अनुसार, एलपीएस के तहत कवर की जा रही डिस्कॉम की बकाया राशि के आधार पर 12 से 48 महीनों तक समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में डिस्कॉम को संस्वीकृत राशि धीरे-धीरे संवितरित की जाएगी।

2) अब तक पीएफसी द्वारा रीवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ) के तहत 11,147 करोड़ रुपए संवितरित किए गए।

- अब तक, पीएफसी ने 18,183 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं और आरबीपीएफ के तहत 11,147 करोड़ रुपए का संवितरण किया है।

3) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) पर अद्यतन

- आरडीएसएस योजना 30.06.2021 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका प्रबंधन पीएफसी और आरईसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएफसी और आरईसी के बीच समान रूप से आवंटित किया गया है। पीएफसी वाले राज्यों में से अब तक 11 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और पंजाब के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी गई है।
- राज्य मंत्रिमंडल की प्रतिबद्धताओं के आधार पर, आरडीएसएस के तहत इन 11 राज्यों के डिस्कॉम को भारत सरकार ने कार्य योजना के संबंध में 1,16,614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। संस्वीकृत परियोजनाओं को अनुदान, इक्विटी और प्रतिपक्ष ऋण के मिश्रण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस दिशानिर्देशों के अनुरूप, 31 दिसंबर, 2022 तक, भारत सरकार अनुदान चरण-1 आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के डिस्कॉम को 1,562 करोड़ रुपए का अग्रिम जारी किया गया है।

घ. ऋण

- 1) 9माह'23 के दौरान, पीएफसी ने घरेलू और विदेशी स्रोतों से कुल 45,639 करोड़ रुपए की राशि जुटाई।
- 2) विविधीकृत वित्तपोषण के अपने फोकस को जारी रखते हुए, पीएफसी ने विदेशी मुद्रा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में सफलतापूर्वक यूएसडी के समतुल्य 1.15 बिलियन डॉलर जुटाए हैं:

- 116 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण का जुटाव किया।
- विदेशी मुद्रा अप्रवासी (बी) ऋण से 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य राशि का जुटाव किया।
- केएफडब्ल्यू, जो जर्मन राज्य के स्वामित्व वाला निवेश और विकास बैंक है, से 59 मिलियन यूरो जुटाए

इसके साथ, 31.12.2022 को पीएफसी का कुल बकाया विदेशी मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो 7.56 बिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य है, जिसमें से 84% यूएसडी मूल्यवर्गित ऋण, 11% जापानी येन और शेष 5% यूरो में हैं। 31.12.2021 तक पोर्टफोलियो के 55% की तुलना में 31.12.2022 तक कुल विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो का लगभग 62% विनिमय जोखिम के लिए हेज किया गया है।

ड. अन्य अद्यतन

1) इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को ऋण संबंधी अद्यतन

25 अगस्त, 2022 को विद्युत मंत्रालय द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को पीएफसी के स्टैंडअलोन नेटवर्थ का 30% तक ऋण देने की मंजूरी दी गई थी।

उपर्युक्त सीमा को 21 दिसंबर, 2022 को संशोधित किया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को कंपनी की बकाया ऋण बही के 30% तक ऋण देने की अनुमति है, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, नई संस्वीकृतियों का 2/3 भाग केवल विद्युत और हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए होना चाहिए।

2) अडानी समूह में पीएफसी के जोखिम पर स्पष्टीकरण

24 जनवरी, 2023 को हिंडेनबर्ग रिसर्च द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया गया है कि पीएफसी का अडानी समूह की किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में कोई एक्सपोजर नहीं है, जिसका उल्लेख हिंडेनबर्ग रिपोर्ट में किया गया है। तथापि, पीएफसी ने अडानी समूह में विभिन्न परियोजना विशिष्ट एसपीवी को 8,314 करोड़ रुपए की बकाया राशि के साथ ऋण प्रदान किया है। इन परियोजना एसपीवी के पास अलग-अलग नकदी प्रवाह और प्रतिभूति फ्रेमवर्क है।

3) पुरस्कार एवं सम्मान

- पीएफसी "सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22" के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष 10 सीपीएसई में से एक है।

- पीएफसी को 'सार्वजनिक सेवा एंटीटी श्रेणी' में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत लेखों/वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कारों में "साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स" गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- पीएफसी को 'सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं' की श्रेणी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई द्वारा लगातार दूसरे वर्ष सम्मानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईसीएआई गोल्ड शील्ड अवार्ड और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईसीएआई सिल्वर शील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया।
